घरेलू मांग से भारतीय अर्थव्यवस्था बम-बम

वित्त मंत्री ने कहा- वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बरकरार, मजबूत घरेलू बाजार बना हुआ है अर्थव्यवस्था का सहारा

नई दिल्ली, 15 जून. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी बढ़ती अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की मजबूत घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है.

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते व्यापारिक हालात और आयात शुल्क में अचानक होने वाले बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं, लेकिन देश का विशाल घरेलू बाजार इन चुनौतियों के प्रभाव को कम करने में सहायक साबित हो रहा है.

यहां आयोजित 'माइंडमाइन सम्मेलन 2026' के एक संवाद सत्र में उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है, लेकिन वैश्विक व्यापार माहौल में अनिश्चितता लगातार बनी हुई है. जिन प्रमुख वस्तुओं का देश बड़े पैमाने पर आयात करता है, उनकी कीमतों और आपूर्ति में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. ऐसे समय में विदेशी मुद्रा भंडार का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है.

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका बड़ा घरेलू बाजार है. घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है. हालांकि विनिर्माण क्षेत्र को आयातित कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन लागत पर दबाव बना हुआ है.

मानसून की स्थिति पर उन्होंने कहा कि अल-नीनो प्रभाव के कारण इस वर्ष कम वर्षा की आशंका जताई जा रही है. हालांकि देश के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार उपलब्ध है और खाद्यान्न संकट जैसी स्थिति की संभावना नहीं है. फिर भी कम बारिश का असर किसानों की आय पर पड सकता है.

> विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव के सवाल पर सीतारमण ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा जुटाने तथा विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों से पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है, जिससे वित्तीय प्रणाली को अतिरिक्त मजबूती मिलेगी.

राखियों ने दिलाई रांची की पूर्णिमा को अलग पहचान

नई दिल्ली, 15 जून रांची की रहने वाली पूर्णिमा ने अपने हुनर और क्रिएटिविटी से हाथ से बनी यूनिक राखियों के जरिए एक अलग पहचान बनाई है. वह रक्षाबंधन के अवसर को ध्यान में रखते हुए दो महीने पहले से ही तैयारियों में जुट जाती हैं और अपने हाथों से ऐसी राखियां बनाती हैं जो डिजाइन और थीम के मामले में बेहद खास होती हैं. उनके कलेक्शन में भाभी के लिए मांगटीका राखी से लेकर भगवान शिव और गणेश जी थीम वाली राखियां भी शामिल हैं, जिनकी शुरुआती कीमत लगभग रु. 40 से होती है.

पूर्णिमा ने अपने इस काम को एक छोटे स्तर से शुरू किया था, लेकिन आज उन्होंने इसे एक ब्रांड का रूप दे दिया है. वह बताती हैं कि उनका सबसे बड़ा फोकस यूनिक डिजाइन बनाने पर रहता है.

मई में थोक महंगाई 9 .68 फीसदी

नयी दिल्ली, 15 जून थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर यानी थोक महंगाई मई में बढ़कर 9.68 प्रतिशत पर पहुंच गयी. अप्रैल में यह 8.26 प्रतिशत पर रही थी.

ये आंकड़े नयी सीरीज के आधार पर जारी किये गये हैं. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अब थोक महंगाई की गणना के लिए आधार वर्ष 2022-23 कर दिया गया है और उसके आधार पर पहली बार आंकड़े जारी किये गये हैं.

थोक महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के दाम में तेज बढ़ोतरी है. इस उपवर्ग में थोक महंगाई दर 61.51 प्रतिशत रही. खनिज तेल की मुद्रास्फीति 49.82 प्रतिशत दर्ज की गयी. वहीं, कोयला और लिगनाइट एक साल में 2.26 प्रतिशत और बिजली 1.85

प्रतिशत सस्ती हुई है. कुल मिलाकर ईंधन एवं ऊर्जा वर्ग की थोक महंगाई दर 30.33 प्रतिशत रही.

विनिर्मित वस्तुओं के वर्ग की महंगाई दर 7.48 प्रतिशत और प्राथमिक वस्तुओं के वर्ग की 4.99 प्रतिशत रही. प्राथमिक वस्तुओं में खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 3.60 फीसदी, अखाद्य पदार्थों की 9.49 फीसदी और खनिजों की 4.91 फीसदी दर्ज की गयी.

> विनिर्मित वस्तुओं में तंबाकू उत्पादों के दाम में सालाना 13 .59 प्रतिशत, रसायन और रासायनिक उत्पादों में 13 .40 प्रतिशत, बुनियादी धातुओं में 12 .30 प्रतिशत, बिजली के उपकरणों में 11 .32 प्रतिशत, विनिर्मित कपड़ों में 10 .22 प्रतिशत और रबड़ तथा प्लास्टिक के उत्पादों में 9 .59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी. नयी सीरीज में 697 की जगह अब 957 वस्तुओं को शामिल किया गया है. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को भी जगह मिली है. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को अब प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी से हटाकर ईंधन एवं बिजली वर्ग में शामिल किया गया है. इसमें अलग-अलग वस्तुओं को दिये जाने वाले भारांश में भी बदलाव किया गया है.

आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर लॉन्च

भोपाल, 15 जून. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर लॉन्च किया है। यह भारतीय जीवन बीमा उद्योग का पहला यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूलिप) है, जिसमें पहले से शामिल गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट दिया गया है।

आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसे उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है, जो टैक्स के लिहाज से बेहतर और गारंटीड फायदे चाहते हैं। इसका ढाँचा बेहद सरल है, एक बार निवेश कीजिए, पॉलिसी अवधि के दौरान लाइफ कवर का लाभ लीजिए और पाँच वर्ष पूर्ण होने पर मैच्योरिटी लाभ पाइए। मैच्योरिटी पर ग्राहक को फंड वैल्यू या गारंटीड मैच्योरिटी बेनिफिट में से जो अधिक होगा, वह मिलेगा। इससे निवेश पर निश्चित और भरोसेमंद रिटर्न मिलता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई 45 वर्षीय ग्राहक एकमुश्त निवेश का विकल्प चुनता है। वह आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर सिक्योर में 5 लाख रुपए निवेश करके पॉलिसी अवधि के दौरान लाइफ कवर का लाभ ले सकता है।

डिजीबर्ड्स 360 : एआई युग की परफॉर्मेंस

नयी दिल्ली, 15 जून सर्च अब सिर्फ एक चैनल नहीं रह गया है. किसी नए कैफे में जाने से पहले आजकल ज्यादातर लोग गूगल पर सर्च करने के बजाय पहले इंस्टाग्राम देखते हैं. वे रील्स और टैग की गई पोस्ट्स के जरिए वहां का माहौल, भीड़ और अनुभव समझते हैं. वहीं, चैटजीपीटी और जेमिनी जैसे एआई प्लेटफॉर्म उत्पादों की जानकारी और रिसर्च के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं.

गूगल के एआई ओवरव्यू भी यह बदल रहे हैं कि लोग सर्च परिणामों को कैसे देखते और समझते हैं. ऐसे में ब्रांड्स के लिए सिर्फ कीवर्ड रैंकिंग हासिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे सर्च इकोसिस्टम में अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करनी होती है—चाहे वह सोशल मीडिया फीड हो या एआई द्वारा तैयार किए गए जवाब.

डिजीबर्ड्स360 एक डेटा-आधारित डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जिसे इसी बदलते डिजिटल युग की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. पारंपरिक एसईओ और पीपीसी सेवाओं के साथ-साथ यह एजेंसी एलएलएम एसईओ, एजेंटिक एआई एसईओ और एआई-संचालित विज्ञापन प्रबंधन जैसी आधुनिक सेवाएं भी प्रदान करती है. डेटा विश्लेषण और रचनात्मक रणनीति के मेल के जरिए यह ब्रांड्स को उन सभी प्लेटफॉर्मों पर अधिक दिखाई देने योग्य बनाती है, जहां उनका लक्षित उपभोक्ता जानकारी खोजता है. एजेंसी की विशेषज्ञता स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में फैली हुई है. इसके ग्राहकों में बजाज मार्केट्स, कार्स24, हेल्थकार्ट, यूरेका फोर्ब्स, जीएसके, मेडिमिक्स, इंडियन मोटरसाइकिल, एमेरिटस और एफएनपी जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं.

> मार्केटिंग अभियानों के संचालन के अलावा डिजीबर्ड्स360 मार्केटिंग टेक्नोलॉजी (मारटेक) सेवाएं भी प्रदान करती है. इनमें जीए4 कंसल्टिंग, कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म (सीडीपी) सेवाएं और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन शामिल हैं. इन सेवाओं की मदद से कंपनियां न केवल यह समझ पाती हैं कि उनकी वेबसाइट पर कौन आ रहा है, बल्कि यह भी जान पाती हैं कि कौन-से कारण आगंतुकों को ग्राहकों में बदल रहे हैं. ऐसे समय में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता खोज और खोजे जाने के तरीकों को पूरी तरह बदल रही है, डिजीबर्ड्स360 ब्रांड्स को भविष्य की डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

भारती एयरटेल ने अफ्रीका स्टेक विलय के लिए समर्थन प्राप्त किया

नई दिल्ली, 15 जून. भारती एयरटेल लिमिटेड ('भारती एयरटेल' या 'कंपनी') ने आज घोषणा की कि उसके लगभग 100% शेयरधारकों ने अपनी प्रमुख रणनीतिक सहायक कंपनी एयरटेल अफ्रीका पीएलसी में हिस्सेदारी के संकलन के लिए चल रहे समझौते को मंजूरी दे दी है, जो भारत की अग्रणी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी में कॉर्पोरेट सुशासन के सर्वोच्च मानकों को रेखांकित करने के साथ-साथ निवेशकों के सुदृढ़ विश्वास को भी पुष्ट करता है।

इस लेन-देन में भारती एयरटेल इंडियन कांटिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, एक प्रमोटर समूह संस्थान, को अधिमान्य आधार पर अपने इक्विटी शेयर जारी कर रहा है, बदले में एयरटेल अफ्रीका में 16.31% हिस्सेदारी लेने के लिए। इस प्रस्ताव को सार्वजनिक एवं संस्थागत निवेशकों सहित शेयरधारकों से अत्यधिक समर्थन प्राप्त हुआ, जो इसके रणनीतिक औचित्य और दीर्घकालिक मूल्य सृजन की संभावनाओं में विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। यह लेन-देन एक नकदी-रहित शेयर अदला-बदली (शेयर स्वैप) है, जो कंपनी को बिना किसी अतिरिक्त ऋणभार अथवा नकदी बहिर्वाह के एक उच्च-वृद्धि वाली परिसंपत्ति में बड़ी हिस्सेदारी अर्जित कर अपनी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

पतंजलि शंखनाद

भारतीय मूल्यों से प्रशासनिक नेतृत्व

हरिद्वार, 15 जून पतंजलि ने भारतीय संस्कृति, आधुनिक विज्ञान और राष्ट्रसेवा की भावना से ओत-प्रोत आईएएस, आईपीएस एवं अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों के निर्माण के उद्देश्य से पतंजलि सिविल सेवा अकादमी के शुभारंभ (शंखनाद) की घोषणा की है.

यह अभिनव पहल प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक प्रशासनिक आवश्यकताओं के समन्वय द्वारा भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगी. अकादमी का उद्देश्य केवल सफल प्रशासनिक अधिकारियों का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि ऐसे राष्ट्रनिष्ठ नागरिक तैयार करना भी है जो भारत माता की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानें. इस दिशा में अकादमी एक करोड़ समर्पित नागरिकों के निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है.

स्वामी रामदेव ने कहा - 'विरासत और विज्ञान' से होगा राष्ट्रीय चरित्र निर्माण. योगऋषि स्वामी रामदेव जी ने इस अकादमी को शिक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी योगदान बताते हुए कहा कि भारत संविधान से संचालित होता है, लेकिन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार अधिकारियों का चरित्र होता है. उन्होंने कहा कि शिक्षा संसार का सबसे बड़ा रचनात्मक कार्य है क्योंकि यह व्यक्ति के मन, चरित्र और नेतृत्व का निर्माण करती है. अकादमी में 'त्रि-शिक्षा' मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान, प्रशासनिक उत्कृष्टता और शैक्षणिक कठोरता का समन्वय होगा. यह मॉडल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की त्रिवेणी की तरह कार्य करेगा. अकादमी का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप 'विरासत और विज्ञान' तथा 'बोधि और शोध' के सिद्धांतों पर आधारित होगा.

आयुष्मान योजना पात्रता मिनटों में जांचें अभी

नई दिल्ली, 15 जून महंगे इलाज और लगातार बढ़ते चिकित्सा खर्चों के बीच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के करोड़ों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर उभरी है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे गंभीर बीमारियों और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो जाता है. हालांकि आज भी बड़ी संख्या में लोगों को यह जानकारी नहीं है कि वे इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं.

सोना और चांदी में आया जोरदार उछाल

2,120 रुपए उछला सोना

4,940 रुपए महंगी हुई चांदी

नई दिल्ली, 15 जून. पश्चिम एशिया में शांति बहाली के संकेतों और अमेरिका-ईरान के बीच संभावित समझौते की उम्मीदों के बीच आज सर्राफा बाजार में तेजी देखने को मिली.

निवेशकों के सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ते रुझान के कारण सोने और चांदी दोनों की

कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया. बाजार आंकड़ों के अनुसार, सोने की कीमत में आज 10 ग्राम पर करीब 2,120 की बढ़ोतरी हुई और यह 1.53 लाख के पार पहुंच गया. वहीं चांदी की कीमतों में भी लगभग 4,940 प्रति किलोग्राम की तेजी देखी गई, जिससे यह नया स्तर छू गई.

भू-राजनीतिक तनाव कम होने और वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के चलते निवेशक फिर से कीमती धातुओं की ओर रुख कर रहे हैं. इसी वजह से सोने-चांदी की मांग बढ़ी है और कीमतों में तेजी आई है.

समाचार विशेष

टीएमसी में दरार, धड़कनें शिंदे की क्यों बढ़ीं?

नई दिल्ली. राजनीति में एक पुरानी कहावत है 'असर बहुत दूर तक होता है.' इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हलचल का सीधा असर हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सियासत पर पड़ता दिख रहा है. पहली नजर में यह कनेक्शन अजीब लग सकता है, लेकिन अगर इन कड़ियों को जोड़कर देखें, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में हो रही टूट का सीधा असर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की 'बार्गेनिंग पावर' पर पड़ने वाला है.

भले ही महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सहयोगियों के भरोसे चल रही है. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जब 240 सीटों पर सिमट गई, तब टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी (आर) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना (7 सांसद) जैसे सहयोगी दल सरकार की रीढ़ बन गए. बीजेपी के बहुमत से चूकने के कारण दिल्ली के दरबार में शिंदे का राजनीतिक वजन अचानक बढ़ गया था. 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने राज्य के भीतर महायुति के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया. बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीतीं, जो शिवसेना की 57 सीटों के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा थीं.

इसी ताकत के अंतर के कारण एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और वे उपमुख्यमंत्री बने, जबकि देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी हुई.

> **टीएमसी के 19 बागी सांसद कैसे बिगाड़ेंगे शिंदे का खेल?**
>
> लोकसभा में जैसे ही टीएमसी के 19 बागी सांसदों के एनडीए को समर्थन देने की औपचारिक घोषणा होगी, दिल्ली में पावर बैलेंस बदल जाएगा. हालांकि बीजेपी को सरकार बचाने के लिए तुरंत नए आंकड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन संसद में एक और बड़ा गुट साथ आने से मौजूदा सहयोगियों पर बीजेपी की निर्भरता कम हो जाएगी. नतीजा यह होगा कि सहयोगियों की ब्लैकमेलिंग या दबाव बनाने की क्षमता कमजोर पड़ेगी. इस पूरे घटनाक्रम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीधा फायदा हो सकता है. केंद्र में सहयोगियों पर निर्भरता कम होते ही, राज्य स्तर के पावर इक्वेशन में भी शिंदे गुट की तरफ से बीजेपी पर दबाव कम हो जाएगा.

मायावती दलित वोटों को जोड़ने में जुटीं

बसपा के संपर्क में सपा के कई सांसद-विधायक?

लखनऊ. सपा के कई सांसदों और विधायकों के बसपा के संपर्क में होने के कयास लगाए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में बीते दिनों में यह नई चर्चा शुरू हो गई है. जिसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाया जा रहा है. इस खबर के पीछे कितनी सच्चाई है इसका दावा तो हम नहीं करते लेकिन चर्चा है कि 2027 में बसपा मजबूत वापसी करने वाली है, इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बसपा के संपर्क में हैं.

इसी साल जनवरी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी में अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा था. सपा

के कद्दावर नेता और नगर पालिका परिषद बाराबंकी के पूर्व अध्यक्ष हफीज भारती ने सपा को छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया था. हाफीज सईद ने इसे घरवापसी कहा था. तो वहीं, उत्तर प्रदेश की गौरीगंज विधानसभा सीट को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह 2027 में बसपा से चुनाव लड़ सकते हैं.

> **बसपा के सामने मजबूत वापसी की चुनौती**
>
> कुल मिलाकर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है. भाजपा के सामने जहां सत्ता को बचाए रखने की चुनौती है तो बसपा के सामने मजबूत वापसी की. बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती सहित पार्टी के तमाम नेता पार्टी के कैडर दलित वोटों को पार्टी से मजबूती से जोड़ने में जुटे हैं. बसपा विधानसभा चुनाव में अपना सबसे बुरा वक्त देख चुकी है. यानी अब पार्टी का प्रदर्शन पहले से बेहतर ही होने की मजबूत संभावना है. ऐसे में अगर बसपा मजबूती से वापसी करने में सफल रहती है तो इससे सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगेगा.

वन टू वन की लड़ाई के मोड में कांग्रेस

नई दिल्ली. साल 2029 का लोकसभा चुनाव भले ही अभी तीन साल दूर हों, लेकिन विपक्षी राजनीति में इसकी तैयारी अभी से दिखाई देने लगी है.

इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक के बाद विपक्षी दलों के बीच एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ चुनावी लड़ाई को किस रणनीति के तहत लड़ा जाए. राजनीतिक संकेत बताते हैं कि कांग्रेस अब 'वन टू वन फाइट' यानी भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार उतारने के मॉडल को आगे बढ़ाना चाहती है. साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल अभी से गोलबंद होने लगे हैं. कांग्रेस इसकी अगुआई कर रही है.

इंडिया अलायंस की बैठक के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और कुछ अन्य सहयोगी दलों ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करने के संकेत दिए हैं. इससे कांग्रेस को विपक्षी एकता के केंद्र में स्थापित करने की कोशिश मजबूत होती दिख रही है. इंडिया अलायंस की बैठक के बाद ममता बनर्जी ने नेशनल लेवल पर कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया. दूसरी तरफ, संजय राउत ने कांग्रेस से अलग हुए दलों से वापस ग्रांड ओल्ड पार्टी में लौटने का आह्वान किया है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की नेता सुप्रिया सुले ने भी कांग्रेस को सपोर्ट करने की बात कही है. इस तरह साल 2029 के संसदीय चुनाव से पहले विपक्षी दल जमीन तैयार करने कोशिश में जुट गए हैं. विपक्ष की रणनीति का मूल विचार यह है कि जिन सीटों पर भाजपा और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला होगा, वहां विपक्षी वोटों का बंटवारा रोका जाए. इसके लिए प्रत्येक सीट पर गठबंधन का केवल एक उम्मीदवार उतारा जाए.

> **सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?**
>
> हालांकि, विपक्षी एकता की तस्वीर जितनी सरल दिखाई देती है, जमीन पर उतनी आसान नहीं है. कई राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी भी रहे हैं. पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के संबंध, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की प्रतिस्पर्धा तथा कुछ राज्यों में क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं सीट बंटवारे को जटिल बना सकती हैं. इसके अलावा विपक्ष को यह भी तय करना होगा कि साझा नेतृत्व का चेहरा कौन होगा. कई दलों का मानना है कि चुनाव परिणाम आने के बाद नेतृत्व का फैसला किया जाना चाहिए.

विशेष | मध्य प्रदेश की सभी 30 सीटें भाजपा के पास ही हैं.

गुजरात से विपक्ष का कोई नहीं होगा

नई दिल्ली. गुजरात के नया राज्य बनने के बाद यह पहली बार होने जा रहा है कि राज्यसभा में गुजरात से विपक्षी पार्टियों का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा. लोकसभा में तो कई बार हो चुका है और कई दूसरे राज्यों से भी हो चुका है.

अभी ही कई राज्य हैं, जहां से लोकसभा में राज्य का कोई प्रतिनिधि नहीं है. मध्य प्रदेश की सभी 30 सीटें भाजपा के पास ही हैं. लेकिन राज्यसभा में आमतौर पर ऐसा कम होता है. गौरतलब है कि नए राज्य के रूप में गुजरात का जन्म 1960 में हुआ था. उसके बाद

66 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं होगा. कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल 21 जून को रिटायर होंगे उसके बाद राज्यसभा में गुजरात का कोई विपक्षी सांसद नहीं होगा.

गुजरात विधानसभा चुनाव में 2017 में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. उसके दो राज्यसभा सांसद थे. लेकिन कोराना के समय अहमद पटेल के निधन के बाद वह सीट उपचुनाव में भाजपा के खाते में चली गई और 2020 में बने शक्ति सिंह गोहिल अब रिटायर हो रहे हैं. मौजूदा विधानसभा में ऐसी स्थिति नहीं है कि विपक्ष कोई सीट जीत सके. आम आदमी पार्टी के कारण पिछले चुनाव में कांग्रेस को 13 फीसदी वोट का नुकसान हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि वह मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं बन पाई उसे सिर्फ 17 सीटें मिलीं. तभी इस बार राज्यसभा की सभी चारों सीटें भाजपा के खाते में चली गईं. गुजरात में तो लगभग सभी सीटें भाजपा के पास हैं लेकिन पंजाब में तो सिर्फ दो विधायक हैं फिर भी छह राज्यसभा सांसद हो गए हैं.